

दैनिक

भारत सरकार द्वारा विज्ञापन हेतु मान्यता प्राप्त

R

मुंबई हलचल

अब हर सच होगा उजागर



महाराष्ट्र में मारी जाएंगी 80 हजार मुर्गियां
6 जिलों पर छाया बर्ड फ्लू का

खतरा

मुंबई। महाराष्ट्र में बर्ड फ्लू का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। राज्य के परभणी जिले में मुर्गियों की मौत की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जिसकी वजह से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार ने बताया कि बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए 80 हजार मुर्गियों को मौत के घाट उतारा जाएगा। इन मुर्गियों को 5 फुट गहरे गड्ढे में केमिकल डालकर दफनाया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य के नागपुर, लातूर, अमरावती, परभणी, नासिक और ठाणे शहर पर बर्ड फ्लू का खतरा छाया हुआ है। उन्होंने बताया कि परभणी शहर की 80000 मुर्गियों को मारा जाएगा। (शेष पृष्ठ 3 पर)

प्रशासन ने परभणी के मुरंबा गांव को कंटेनमेंट जोन किया घोषित

ठाणे शहर से भी जांच के लिए नमूने भेजे गए

महाराष्ट्र के परभणी जिले के बाद मुंबई से सटे ठाणे शहर के कई इलाकों से नमूनों को जांच के लिए भेजा गया है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ठाणे शहर में बर्ड फ्लू का खतरा किस स्तर पर है। सुनील केदार ने सभी पोल्ट्री व्यवसायियों को यह भरोसा दिलाया है कि उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। इसके पहले भी साल 2006 में राज्य में बर्ड फ्लू का खतरा छाया था। उस समय भी राज्य सरकार ने पोल्ट्री व्यवसायियों की मदद की थी। पोल्ट्री व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम भाग है। इस अर्थव्यवस्था को डूबने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि केंद्र सरकार का इंतजार ना करते हुए महाराष्ट्र सरकार उनकी मदद करेगी।

मकर संक्रांती के शुभ अवसर पर

तील लड्डू Scheme Valid upto: 20-01-21
₹ 340/- 260/- Per Kg.

शुद्ध घी में बना केसरीया **घेवर**

MM MITHAIWALA
Malad (w) Tel.: 288 99 501

बीएमसी स्कूलों में बांटे जाएंगे 75 लाख मास्क, 15 जनवरी से खुलेंगे स्कूल (समाचार पृष्ठ 3 पर)

किसान आंदोलन

केंद्र ने दाखिल किया हलफनामा

आज 'सुप्रीम' आदेश दे सकती है कोर्ट

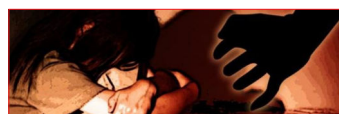


संवाददाता

नई दिल्ली। किसान आंदोलन मामले में सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक हलफनामा दाखिल किया है। केंद्र ने कोर्ट से कहा कि प्रदर्शनकारियों की 'गलत धारणा' को दूर करने की जरूरत है। कृषि मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रदर्शनकारियों में यह गलत धारणा है कि केंद्र सरकार और संसद ने कभी भी किसी भी समिति द्वारा परामर्श प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्दों की जांच नहीं की है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

महाराष्ट्र में 'निर्भया' जैसी वारदात

चलती बस में युवती के साथ रेप



वाशिम। महाराष्ट्र के वाशिम जिले से बलात्कार का एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जिसने दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड की याद ताजा कर दी। वहां सड़क पर चलती एक लम्बरी बस में एक लड़की के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी ने लड़की के साथ एक बार नहीं बल्कि दो बार रेप किया और उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। (शेष पृष्ठ 3 पर)

हमारी बात



कौओं-परिंदों की चिंता

देश के सात से अधिक राज्यों में बर्ड फ्लू के कारण सैकड़ों पक्षियों का मरना या मारा जाना दुखद तो है ही, मानवता पर प्रश्नचिह्न भी है। बेजुबान पक्षियों में भी कौओं की बड़ी संख्या में मौत झकझोर रही है। कौओं की चिंता इसलिए भी ज्यादा है, क्योंकि अक्वल तो शहरों में उनकी संख्या बहुत घट चुकी है, गांवों में भी वे पहले की तरह नजर नहीं आते हैं। ऐसे में, उनकी मौत बाकी बचे हुए कौओं को मानव बस्तियों से बहुत दूर कर देगी। कौओं के साथ मानव बस्तियों का रिश्ता पुराना है। वे सदियों से सफाईकर्ता के रूप में हमारे आसपास से नाना प्रकार के जहरीले या अवांछित कीड़े-मकोड़ों को हटाते आए हैं। उनका हमारे पास न होना, हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है। कौओं की मौत की सूचना राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से विशेष रूप से आ रही है। विशेषज्ञ जांच में लगे हैं, लेकिन सामान्य रूप से कौओं में बर्ड फ्लू का संक्रमण दूसरे पक्षियों से ही हुआ होगा। आमतौर पर कौओं को दूसरे पक्षियों, जंतुओं के शव खाते-उठाते देखा जाता है, इसी वजह से उनमें संक्रमण की गुंजाइश ज्यादा रहती है। इस बार ज्यादा आशंका यह है कि विदेशी पक्षियों के जरिए ही बर्ड फ्लू का देश में संक्रमण हुआ है। सर्दियों में बड़ी संख्या में विदेशी पक्षी भारत के ताल, तालाबों, खेतों में समय बिताने आते हैं। कुछ पक्षी तो यहां सर्दियों के समय चार से पांच महीने तक रहते हैं। ऐसे में, यह बहुत जरूरी है कि विदेशी पक्षियों की खास तौर पर निगरानी की जाए। ताल-तालाबों के आसपास नजर रखने के साथ ही साफ-सफाई के काम को मुस्तैदी से अंजाम देना होगा। यह वही मौसम है, जब किसी न किसी राज्य से बड़ी संख्या में पक्षियों की मौत की खबर आती है, अतः संबंधित महकमों और विशेषज्ञों को सचेत हो जाना चाहिए। बर्ड फ्लू अत्यधिक गंभीर संक्रामक और श्वसन रोग है, जो मनुष्यों में फैला, तो बहुत घातक स्वरूप में सामने आएगा। इस साल बर्ड फ्लू की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना से तबाह अर्थव्यवस्था और झटके झेलने की स्थिति में नहीं है। प्रशासन को वाकई हाई अलर्ट पर रहना होगा। बर्ड फ्लू अर्थात एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप को रोकने के लिए अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों के दो-तीन किलोमीटर के दायरे में बत्खों, मुर्गियों, पक्षियों आदि पर निगाह रखनी पड़ेगी। देश में जहां से भी बर्ड फ्लू की सूचना मिले, वहां सावधानी से उतने ही पक्षियों को मारना चाहिए, जितना बहुत जरूरी हो। जहां बर्ड फ्लू का संक्रमण नहीं हुआ है, वहां घबराने की जरूरत नहीं, पर सतर्क रहकर पक्षियों और उनकी गतिविधियों पर नजर रखनी चाहिए। जहां कौए हैं, वहां उनके लिए दाना-पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि उन्हें अन्य पक्षियों-कीड़ों के शव के पीछे घात न लगाना पड़े। हमें पक्षियों के स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होना चाहिए। भारत एक ऐसा देश है, जहां सदियों से मेहमान पक्षी आते रहे हैं, अतः भारत में प्रवासी पक्षियों के स्वास्थ्य के अलावा स्वदेशी पक्षियों की भी चिंता जरूरी है। विशेष रूप से मानव व मानव आबादी को पसंद करने वाले कौओं को बचाने के लिए हरसंभव प्रयास जरूरी हैं। कौओं में भी कुछ प्रजातियां विरल हो चली हैं, बर्ड फ्लू के बहाने ही सही, उनके लिए संवेदना बढ़े, तो हम मनुष्यों का ही भला होगा।

कानूनी मकड़जाल में उलझता आंदोलन

केंद्र सरकार के बनाए तीन कृषि कानूनों और 46 दिन से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी। उसके चार दिन के बाद केंद्र सरकार के साथ किसानों की फिर से वार्ता होनी है। केंद्र के साथ हो रही वार्ताओं से अब तक कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और जल्द ही आठ जनवरी की वार्ता में केंद्र ने बहुत साफ इशारा कर दिया कि सर्वोच्च अदालत से इस मामले का समाधान कराया जाए। किसान सुप्रीम कोर्ट जाना नहीं चाह रहे हैं। उन्होंने कहा हुआ है कि विवाद उनके और सरकार के बीच है इसलिए वे अदालत नहीं जाएंगे, आंदोलन करते रहेंगे। किसानों के लिए यह 'कैच 22 सिचुएशन' की तरह स्थिति है। अदालत में एक के बाद एक दायर हो रही याचिकाओं, सर्वोच्च अदालत की कोरोना के खतरों को लेकर की गई तबलीगी जमात वाली टिप्पणी और सरकार के रुख से उनकी उलझन बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है कि सरकार ने किसानों को अंतहीन वार्ताओं में उलझा कर जो जाल बुना उसमें किसान फंस रहे हैं। उनके पास उनकी ईमानदारी, खुदारी और मृत्यु होने तक संघर्ष करने की जिजीविषा के अलावा और कुछ नहीं है।

उनकी हिम्मत है, जो वे दिल्ली के शून्य तक पहुंचे तापमान, कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू के खतरे उठा कर आंदोलन कर रहे हैं। पर दूसरी ओर सरकार साम, दाम, दंड और भेद सबका इस्तेमाल कर रही है। वह जाने कहां कहां से लाकर किसान संगठन खड़े कर रही है और उनसे कानूनों का समर्थन करा रही है, किसान संगठनों में फूट डाल रही है, मीडिया के जरिए माहौल बना कर आंदोलन को बदनाम कर रही है और अदालत से मनमाफिक फैसला हासिल करने के लिए पूरे मुद्दे को तोड़-मरोड़ रही है। असल में केंद्र सरकार के बनाए कृषि कानूनों के दो पहलू हैं, जिनमें एक संवैधानिकता का पहलू है और दूसरा व्यावहारिक रूप से खेती-किसानी पर होने वाले असर का पहलू है। किसान इस दूसरे पहलू को लेकर ज्यादा चिंतित हैं। वे कृषि कानूनों की संवैधानिकता की बहस में नहीं पड़ना चाह रहे हैं। तभी उन्होंने कहा है कि वे अदालत नहीं जाएंगे। उनको पता है कि अदालत संवैधानिकता पर तो विचार कर सकती है लेकिन किसी कानून की जरूरत है या नहीं इस पर वह सरकार के फैसले में



दखल नहीं दे सकती है। सरकार यहीं चाहती है कि सर्वोच्च अदालत में कानूनों की संवैधानिकता पर जल्दी से सुनवाई हो जाए और उसका फैसला आ जाए। सरकार को यकीन है कि इस बिंदु पर उसका पक्ष मजबूत है क्योंकि उसका कहना है कि उसने कृषि उत्पादों की बिक्री को लेकर कानून बनाए हैं, जो संविधान की समवर्ती सूची में हैं। और दूसरे, इसे संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया है।

परंतु संवैधानिकता के मामले पर भी केंद्र सरकार का पक्ष कमजोर है क्योंकि कृषि का मामला संविधान की राज्य सूची में रखा गया है। इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को है। सरकार कृषि पैदावार के कारोबार को लेकर तो कानून बना सकती है पर कृषि को लेकर कानून नहीं बना सकती। अब सवाल है कि कृषि कार्य का दायरा कहां तक है? क्या किसान खेत में फसल बो देगा और फसल हो जाने के बाद काट लेगा, इतना ही कृषि कार्य है? नहीं! फसल खेत से खलिहान तक लाना और उसे किसी के भी हाथों बेचना किसान का अधिकार है और यह कृषि कार्य में आता है। जब किसान किसी को अपनी फसल बेच दे उसके बाद उसका जो भी कारोबार होगा वह कृषि कार्य के दायरे से बाहर होगा और केंद्र सरकार उस पर कानून बना सकती है। अगर ईमानदारीपूर्वक इस व्याख्या को माना जाए तो केंद्र का बनाया कानून असंवैधानिक हो जाएगा। केंद्र सरकार ने किसानों के फसल बेचने के अधिकार को भी कारोबार की श्रेणी में रखा है और इसलिए कानून बनाया है, जबकि किसान का अपनी फसल बेचना कृषि कार्य है, कारोबार नहीं है। इस कानून की संवैधानिकता को लेकर दूसरा सवाल इसे संसद से पास कराने के तरीके पर है। देश में कोई भी कानून बनाने से पहले उसका मसौदा तैयार किया जाता है, मसौदा तैयार करने में उस सेक्टर के लोगों और जानकारों की राय ली जाती है, जिनके लिए कानून बनाया जाता है, मसौदा तैयार होने के बाद उसे

आम लोगों के विचार के लिए सार्वजनिक किया जाता है और लोगों से आपत्ति मंगाई जाती है और तब संसद में पेश किया जाता है। संसद में भी उस पर विस्तार से चर्चा होती है और विवाद होने की स्थिति में संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति को या प्रवर समिति को भेजा जाता है। केंद्र सरकार ने कृषि कानून बनाने में इनमें से ज्यादातर की अनदेखी की है। किसान संगठनों का कहना है कि उनकी राय नहीं ली गई है और विपक्ष का कहना है कि उनकी बात नहीं सुनी गई। लोकसभा में अपने प्रचंड बहुमत के दम पर सरकार ने इसे पास कराया और राज्यसभा में बहुमत नहीं होने के बावजूद विपक्ष की आपत्तियों को दरकिनार कर बिना वोटिंग कराए, जोर-जबरदस्ती और एक तरह से अवैध तरीके से बिल पास कराया गया। यह संभवतः पहली बार हुआ कि विपक्ष वोटिंग की मांग करता रहा और आसन ने बिना वोटिंग कराए, ध्वनि मत से बिल पास कराया। नियम यह कहता है कि एक भी सदस्य अगर किसी बिल पर वोटिंग की मांग करता है तो अनिवार्य रूप से वोटिंग होगी। कृषि कानूनों पर समूचा विपक्ष वोटिंग की मांग करता रहा और आसन पर विराजमान उप सभापति ने उसे ठुकरा कर ध्वनि मत से बिल पास कराया। पहले तो सरकार ने अध्यादेश के जरिए इन कानूनों को लागू किया और फिर कानून बना कर जोर-जबरदस्ती इन्हें संसद से पास कराया। सो, अगर ईमानदारी से इन कानूनों की संवैधानिकता पर विचार होता है तो ये कानून खारिज होंगे। तभी अगर सुप्रीम कोर्ट कानूनों की संवैधानिकता पर सुनवाई के लिए तैयार हो जाती है तो फिर यह मामला लंबा चलेगा। क्योंकि कई राज्य सरकारें भी इन कानूनों की संवैधानिक वैधता का मुद्दा लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगी। पंजाब सरकार ने कहा है कि वह जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका देगी। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़, केरल आदि राज्यों की सरकारों ने केंद्र के बनाए कानूनों को निरस्त करने का प्रस्ताव विधानसभा से पास किया है और अपने कानून बनाए हैं। संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक केंद्र के बनाए किसी कानून के विरोध में अगर राज्य सरकार कानून बनाती है तो उसे राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी होगी। अभी तक किसी राज्य के बनाए कानून पर राष्ट्रपति का फैसला नहीं हुआ है। देर-सबेर इन राज्यों को भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है।

वॉट्सऐप का विश्वासघात!

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म वॉट्सऐप की नई पॉलिसी को लेकर दुनिया भर में इसके यूजर्स में पैदा हुआ गुस्सा जायज है। खासकर वॉट्सऐप के इस कदम का भारत में असर देखा जाएगा, जो इस प्लैटफॉर्म का सबसे बड़ा मार्केट है। वॉट्सऐप ने अब यूजर्स के सामने सिर्फ दो ही विकल्प छोड़े हैं- या तो वे उसकी शर्तें मान कर अपनी प्राइवेसी को खत्म करें या फिर अपना अकाउंट डिलीट करें। शर्तें मानना है या नहीं, इस बारे में सोचने के लिए 8 फरवरी तक का वक्त वॉट्सऐप की मालिक कंपनी फेसबुक ने दिया है। गौरतलब है कि दुनियाभर में 200 करोड़ से ज्यादा यूजर्स वॉट्सऐप इस्तेमाल करते हैं। नया साल शुरू होते ही यूजर्स को वॉट्सऐप पर नए टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी का अपडेट मिलने लगा। इसमें लिखा है कि यूजर्स को ये पॉलिसी माननी होगी। इसमें मूल बात यह है कि वॉट्सऐप पर आप जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर, सेंड या रिसीव करते हैं, कंपनी उन्हें कहीं भी यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकती



है। जाहिर है, इस पॉलिसी के जरिए वॉट्सऐप अपने 200 करोड़ से ज्यादा यूजर्स का डेटा एक्सेस कर पाएगी। यानी वो उनके डेटा को दूसरे प्लैटफॉर्म पर शेयर भी कर पाएगी। नई पॉलिसी के नोटिफिकेशन में उसने साफ लिखा है कि अब वॉट्सऐप आपकी हर सूचना अपनी पेरेंट कंपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर करेगा। यानी वॉट्सऐप अपने यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकती है। दूसरी तरफ यूजर्स की प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। मसलन, भुगतान के लिए वॉट्सऐप का इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के बैंक का नाम, कितनी राशि और

डिलीवरी का स्थान सभी को ये प्लैटफॉर्म ट्रैक करेगा। इससे फेसबुक-इंस्टाग्राम भी आपके फाइनेंशियल ट्रैजिक्शन जान जाएंगे। ट्रैजिक्शन डिटेल से कंपनी आपको प्रोफाइलिंग करेगी। यानी आपकी आर्थिक हालत कैसी है। अगर वॉट्सऐप और फेसबुक के आकलन में आप अमीर दिखें, तो फिर आपको महंगी गाड़ियों के विज्ञापन दिखने लगेंगे। वॉट्सऐप ने विकल्प दिया है कि यूजर अपनी लोकेशन एक्सेस डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि उसने यह भी कहा है कि आईपी एड्रेस और मोबाइल नंबर से अंदाजा लग जाएगा, आप कब-कहां जाते हैं। फिर वॉट्सऐप यूजर का स्टेटस भी पढ़ेगा। इससे मिली जानकारी का इस्तेमाल भी यूजर्स की प्रोफाइलिंग के लिए किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बिना यूजर्स की सहमति लिए वॉट्सऐप ने अपनी पॉलिसी बदल ली है। कह दिया कि इसे मानना है तो ठीक, वरना हमारे प्लैटफॉर्म से जाओ। क्या यह एक तरह का विश्वासघात नहीं है?

बीएमसी स्कूलों में बांटे जाएंगे 75 लाख मास्क, 15 जनवरी से खुलेंगे स्कूल



मुंबई। मुंबई शहर में आगामी 15 जनवरी से स्कूलों को खोलने की तैयारी बीएमसी ने की है। ऐसे में जब छात्र स्कूल पहुंचेंगे तो मनपा प्रशासन उन्हें कपड़े का सिला हुआ मास्क देगी। इस मास्क को छात्र धुल भी सकेंगे। बीएमसी के स्कूल में

पढ़ने वाले लाखों छात्रों को इससे फायदा होगा और कोरोना महामारी के खतरे से वे दूर रहेंगे। बीएमसी ने इसके लिए 75 लाख मास्क खरीदने का फैसला किया है। मुंबई महानगरपालिका के द्वारा संचालित स्कूलों में तकरीबन दो लाख 96

हजार छात्र शिक्षा लेते हैं। ऐसे में जब वे स्कूल आएंगे तब उन पर कोरोना महामारी का खतरा ना हो। इसलिए बीएमसी ने यह फैसला लिया है। इतनी भारी तादात में मास्क खरीदने के लिए बीएमसी 20 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

मुंबई में कोरोना नियंत्रित: मुंबई शहर में फिलहाल कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। शहर में कोरोना नियंत्रण में है और अनलॉक में मिली सहूलियतों के बाद जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। लिहाजा बच्चों की सेहत का ध्यान रखते हुए बीएमसी ने यह एहतियाती कदम उठाया है। आपको बता दें कि बीएमसी के स्कूलों में ज्यादातर गरीब तबके के छात्र पढ़ाई करते हैं। कोरोना महामारी की वजह से कई लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। वहीं कई लोगों की तनखाह में कटौती की गई है। ऐसे में मनपा प्रशासन का यह कदम सराहनीय है।

बीएमसी की मास्क मुहिम: छात्रों को मास्क मुहैया करवाने के लिए बीएमसी ने अगले 2 साल तक मास्क खरीदने का निर्णय लिया है। बीएमसी प्रशासन की तरफ से इस बाबत टेंडर भी जारी कर दिया गया है। कोरोना महामारी के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है ताकि छात्रों को मास की किल्लत ना होने पाए।

महाराष्ट्र: कॉलेज खोलने पर निर्णय 20 जनवरी तक

मुंबई। कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते राज्यभर के बंद कॉलेजों को खोलने की कवायद शुरू हो गई है। उच्च शिक्षा व तकनीकी मंत्री उदय सामंत राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ चर्चा करके 20 जनवरी से पहले कॉलेजों को खोलने को लेकर निर्णय लेंगे। सामंत ने कहा कि 20 जनवरी तक 50 फीसद विद्यार्थियों की उपस्थिति अथवा एक विशेष मानक संचालन (एसओपी) के जरिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोलने को लेकर विचार किया जा रहा है। सरकार उन सभी



बिंदुओं पर ध्यान देगी जो विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर जरूरी होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना वायरस के चलते यूनिवर्सिटी और कॉलेज बंद हैं, लेकिन

अब स्थिति नियंत्रण में है और टीकाकरण शुरू हो रहा है। इसीलिए, यूनिवर्सिटी और कॉलेज को खोलने के लिए पहले हॉस्टल, कॉलेजों में बने क्वारंटीन सेंटर, स्थानीय परिस्थिति आदि जायजा लिया जाएगा, इसके बाद ही यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने शनिवार को यूनिवर्सिटी, कॉलेज खोलने, प्राध्यापकों की भर्ती, कॉलेजों की समस्या और प्रवेश प्रक्रिया में आई तकनीकी खामियों को लेकर फेसबुक के माध्यम से विद्यार्थी, प्राचार्य और प्राध्यापकों से संवाद किया।

प्राचार्यों की भर्ती के लिए अनुमति: मंत्री सामंत ने कहा कि लॉकडाउन में कॉलेजों में प्राचार्यों की भर्ती को टालने के लिए जीआर जारी किया था, लेकिन अब सरकार ने अनुदानित कॉलेजों में रिक्त पड़े 260 प्राचार्यों की भर्ती को अनुमति दे दी है। इससे कॉलेजों के संचालन में मदद मिलेगी।

प्राध्यापकों की भर्ती पर निर्णय जल्द: संवाद के दौरान कई लोगों ने प्राध्यापकों की भर्ती को लेकर सवाल किए। इस पर सामंत ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते वित्त विभाग ने प्राचार्य और प्राध्यापकों की भर्ती नहीं करने के लिए सर्कुलर जारी किया था, लेकिन अब सरकार ने प्राचार्य की भर्ती को लेकर निर्णय ले लिया है। बाकी भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। इसीलिए, सभी संवैधानिक भर्ती के लिए जल्द ही निर्णय लिया जाएगा।

टॉय ट्रेन ने बढ़ाई रेलवे की कमाई, दो महीने में 50 हजार लोगों ने लिया टॉय ट्रेन का मजा

मुंबई। करीब दो महीने पहले अमन लॉज से माथेरान के बीच फिर से शुरू की गई टॉय ट्रेन का मजा पचास हजार से ज्यादा यात्री ले चुके हैं। मुंबई से सटे इस छोटे से हिल स्टेशन तक पहुंचने वालों ने रेलवे की कमाई बढ़ाने के साथ ही, माथेरान में रौनक लौटाई है। कोरोना बंधनों के चलते ये छोटा सा हिल स्टेशन आठ महीनों तक सूना पड़ा रहा। अब मध्य रेलवे ने अमन लॉज से माथेरान के बीच दोबारा पहाड़ों की रानी यानी टॉय ट्रेन चलाई है। रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, करीब दो महीने पहले हुई इस शुरूआत का ये असर रहा कि 53 हजार से ज्यादा यात्रियों ने अब तक इसका लुफ्त उठाया है। कोविड की पृष्ठभूमि के बावजूद अमन लॉज-माथेरान खंड पर संचालित हो रही टॉय ट्रेन की शटल सेवाओं में यात्री काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 14 नवंबर, 2020 को 4 शटल सेवाओं के साथ इस खंड में परिचालन शुरू करने के बाद से 53,679 यात्रियों और 5,864 पैकेजों का परिवहन किया है। इस गंतव्य के लिए पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि के कारण, सेवाओं को धीरे-धीरे बढ़ाया गया।



(पृष्ठ 1 का शेष)

महाराष्ट्र में मारी जाएंगी 80 हजार मुर्गियां

राज्य और जिलों में बर्ड फ्लू के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए परभणी के मुर्बा गांव में तकरीबन 80 हजार मुर्गियों को शाम तक मौत के घाट उतार दिया जाएगा। परभणी जिला के मुर्बा गांव में तकरीबन 800 मुर्गियों की हाल में मौत हो गयी थी। अचानक इतनी भारी तादात में मुर्गियों के मरने से स्थानीय प्रशासन सकते में आ गया था। आनन-फानन में इन सभी मुर्गियों के नमूने भोपाल स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे। वहां से यह पता चला है कि इन मुर्गियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। इस वजह से प्रशासन ने मुर्बा गांव के एक किलोमीटर के दायरे में तकरीबन 80 हजार मुर्गियों को मारने का आदेश दिया है। इस आदेश के तहत आज शाम तक इन 80 हजार मुर्गियों को मारकर जेसीबी की मदद से गड्ढा खोदकर दफना दिया जाएगा। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मुर्बा गांव को बर्ड फ्लू के खतरे के महेनजर प्रतिबंधित क्षेत्र यानी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस गांव में और आसपास में मुर्गियों की बिक्री और खरीदी पर रोक लगा दी गई है। इसी प्रकार मुर्गियों को एक जिले से दूसरे जिले में लेकर जाने और आने पर भी रोक लगा दी गई है। इसी प्रकार इस गांव में अंडों की बिक्री और खरीद पर भी प्रशासन ने रोक लगा दी है। बर्ड फ्लू के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र के पशु संवर्धन

मंत्री सुनील केदार ने जनता से आग्रह किया है की अगर चिकन या अंडे खाने हैं तो सबसे पहले उन्हें 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कम से कम आधा घंटा पकाएं उसके बाद में ही उसे खाएं। इतनी डिग्री पर पकाने के बाद बर्ड फ्लू के जीवाणु मर जाते हैं।

किसान आंदोलन....

हलफनामे में यह भी कहा गया है कि कानून जल्दबाजी में नहीं बने हैं बल्कि ये तो दो दशकों के विचार-विमर्श का परिणाम है। देश के किसान खुश हैं क्योंकि उन्हें अपनी फसलें बेचने के लिए मौजूदा विकल्प के साथ एक अतिरिक्त विकल्प भी दिया गया है। इससे साफ है कि किसानों का कोई भी निहित अधिकार इन कानूनों के जरिए छीना नहीं जा रहा है। हलफनामे में आगे कहा गया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमी को दूर करने के लिए किसानों के साथ जुड़ने की पूरी कोशिश की है और किसी भी प्रयास में कमी नहीं की है। दिल्ली की सरहद पर पिछले 47 दिनों से जमे प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा 26 जनवरी को ट्रेक्टर रैली निकालने की मंशा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने अर्जी दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में केंद्र सरकार ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों के द्वारा ट्रेक्टर रैली न निकालने का आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे।

महाराष्ट्र में 'निर्भया' जैसी वारदात

पीडित युवती ने इस संबंध में पुणे के राजनगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुणे पुलिस ने वहां जीरो एफआईआर दर्ज कर उसे घटना स्थल वाले जनपद वाशिम के मालेगांव में पुलिस को भेज दिया है। अब वहां की पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। 24 साल की पीडिता ने पुलिस को बताया कि वह एक प्राइवेट स्लीपर कोच बस से यात्रा कर रही थी। बस नागपुर से पुणे जा रही थी। इसी दौरान बस के क्लीनर ने उसे 5 नंबर सीट से उठाकर 15 नंबर की सीट पर बैठने के लिए कहा। जब युवती वहां चली गई तो वो उसके पास पहुंचा और उसे चलती बस से नीचे फेंकने की धमकी देकर उसके साथ 2 बार बलात्कार किया। पुलिस ने युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज करने के बाद कार्रवाई शुरू कर दी। इसी के चलते मालेगांव पुलिस ने उस बस को पुणे से कब्जे में ले लिया, जिसमें वारदात को अंजाम दिया गया था। अब पुलिस की टीम आरोपी क्लीनर को गिरफ्तार करने के लिए नागपुर रवाना की गई है। मालेगांव की पुलिस अधिकारी पुष्पलता वाघ ने जानकारी देते हुए बताया कि पीडित युवती गोदिया इलाके की रहने वाली है। वह पुणे के कोरेगांव में मौजूद एक निजी कंपनी में काम करती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल तेजी से कर रही है। लड़की का मेडिकल कराने के बाद उसे घर भेज दिया गया है।



भायंदर पश्चिम के बावन जिनालय मंदिर में भक्तों ने किये दर्शन, इस अवसर पर मुंबई मास् टाइम्स के संपादक रविंद्र जैन भगवान के और गुरुदेव के दर्शन किए भक्ति प्रोग्राम का लाभ लिया।

आशिकी फेम राहुल रॉय संग पायल गोगोई, जोया खान, ताहिर कमाल खान, प्रोड्यूसर स्नेहा गोगोई का म्यूजिक वीडियो 'जान कद लेय गई' हुआ आउट

एस के फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी बॉलीवुड म्यूजिक वीडियो 'जान कद लेय गई' आउट कर दिया गया है। यह म्यूजिक वीडियो अल्ट्रा बॉलीवुड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है, जो रिलीज के बाद से वायरल हो रहा है। इस म्यूजिक वीडियो में बॉलीवुड हीरोइन पायल गोगोई हैं, तो बॉलीवुड की ब्लॉक बस्टर फिल्म आशिकी फेम अभिनेता राहुल रॉय भी इसमें नजर आये हैं पायल गोगोई को अपने इस म्यूजिक वीडियो से काफी उम्मीदें हैं। इसलिए उन्होंने इसके आउट होने से पहले ही दर्शकों से जरूर देखने की अपील की और कमेंट करने को भी कहा। लेकिन अब जब ये गाना रिलीज हो चुका है, तब पायल गोगोई ने कहा कि यह मेरे लिए बेहद खास है। हमने इसके लिए खूब मेहनत भी की है। वहीं राहुल रॉय भी इस



म्यूजिक वीडियो में हैं। उनके साथ काम करने में भी मजा आया है। वे हमारे सिनियर हैं, मगर बेहद डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने भी इस म्यूजिक वीडियो में शानदार काम किया है। उम्मीद है आपको यह म्यूजिक वीडियो पसंद आएगी। पायल गोगोई ने बताया कि म्यूजिक वीडियो 'जान कद लेय गई' की प्रोड्यूसर स्नेहा गोगोई हैं। को-प्रोड्यूसर प्रवीण सोलंकी हैं। इसमें मेरे और राहुल रॉय के अलावा ताहिर कमाल और जोया खान भी हैं। इसका खूबसूरत म्यूजिक बिक्रमजीत रांझा ने दिया है। वीडियो कोरियोग्राफर राजू राय हैं। डायरेक्टर आजाद हुसैन हैं। डीओपी हेमंत पाटिल हैं। इस म्यूजिक वीडियो की शूटिंग भारी भरकम सेट लगाकर की गई है और अब यह आप सबों के सामने है। इसलिए इसे आप जरूर देखें और अपना प्यार दें। अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें।

अमेरिका: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग को संसद भी तैयार



वाशिंगटन। अमेरिकी संसद भवन में पिछले बुधवार को हुई हिंसा के लिए प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हुए उन पर महाभियोग का मसौदा तैयार कर लिया है। अध्यक्ष नैसी पेलोसी का ट्रंप को पद से हटाने के लिए 25वें संशोधन के लिए पत्र लिखने के बाद डेमोक्रेट एकजुट हो गए हैं। यह संशोधन उपराष्ट्रपति व बहुमत सदस्यों को अधिकार देता है कि वे ट्रंप को हटाएं। हालांकि रिपब्लिकनों के रुख अभी साफ नहीं है। लेकिन कांग्रेस सदस्य ब्रेड शनीडर ने कहा है, मैं राष्ट्रपति पर उनके अपराधों के लिए महाभियोग प्रस्ताव पेश करने में मदद करना चाहूंगा। जबकि प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष

नैसी पेलोसी ने आरोपों का मसौदा संसद में रखने से पहले कहा कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें तत्काल कदम उठाना होगा क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप के पद पर रहने से संविधान को खतरा है। पेलोसी की टीम ने 25वां संशोधन लागू करने के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेस और कैबिनेट के सदस्यों से देर शाम इस मसौदे पर मतदान को कहेंगी। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है इसलिए इसके विचार पर आपत्ति आ सकती है। इसके बाद पेलोसी मंगलवार को पूर्ण सदन के सामने प्रस्ताव रखेंगी। इसे पारित करने के लिए पेंस और कैबिनेट के पास महाभियोग की कार्यवाही से पहले 24 घंटे का समय होगा।

फर्जी तरीके से लाभ लेने वालों से वसूली प्रक्रिया शुरू

संवाददाता

नई दिल्ली

पीएम किसान योजना

सूची एक साल को मान्य

यदि आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में गलत तरीके से लाभ उठाया है तो अब आपको यह रकम वापस करनी होगी। आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना के तहत पता चला है कि इस योजना में 20 लाख से अधिक अयोग्य लाभार्थी पाए गए हैं। सरकार की ओर से इन्हें 1364 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। अब इन लोगों की किस्तें रोक दी गई हैं और इनसे वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पीएम किसान सम्मान निधि की सूची केवल एक साल के लिए ही मान्य रहती है। इसके बाद सूची को अपडेट किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसानों ने अपनी जमीन वेच दी या फिर कोई जमीन खरीदी। टैक्सपेयर को भी सूची से बाहर कर दिया जाता है। इस स्थिति में पात्रता बदलती रहती है। सरकार इस योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए हर साल इस लिस्ट को अपडेट करती है।



किसानों के लिए वर्ष 2019 में शुरू की गई थी यह योजना

तीन बराबर किस्तों में दिए जाते हैं कुल 6000 रुपए

क्यों रोकी गई किस्तें

कृषि मंत्रालय ने बताया कि अयोग्य लाभार्थियों की दो श्रेणियों की पहचान की गई है जिनमें पहले 'अर्हता पूरी नहीं करने वाले किसान' हैं जबकि दूसरी श्रेणी 'आयकर भरने वाले किसानों' की है। अब इन लोगों की किस्तें रोक दी गई हैं।



योजना की पात्रता

पीएम किसान योजना में सरकारी नौकरियों करने वाले जनप्रतिनिधि, इन्कम टैक्स के दायरे में आने वाले लोग शामिल नहीं हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी खेती योग्य जमीन पर खेती भले नहीं करते हो लेकिन उन्हें भी इस स्कीम का फायदा मिल सकता है।

कहां कितने अयोग्य लाभार्थी

20 लाख 48 हजार अयोग्य लोगों ने उठा लिया योजना का लाभ	44% अयोग्य लाभार्थियों में योजना की अर्हता पूरी नहीं करते किसान
1364 करोड़ रुपए का किया जा चुका है सरकार की ओर से भुगतान	55% से अधिक अयोग्य लाभार्थी आते हैं आयकरदाता की श्रेणी में
पंजाब 4.74 लाख	असम 3.45 लाख
महाराष्ट्र 2.86 लाख	गुजरात 1.64 लाख
उत्तर प्रदेश 1.64 लाख	



पूर्वी लद्दाख में भीषण ठंड से चीन का 'छूटा पसीना', एलएसी से हटाए 10 हजार सैनिक

नई दिल्ली। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चल रहे सीमा विवाद के बीच चीन ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) से अपने 10 हजार सैनिकों को हटा दिया है। कहा जा रहा है कि चीन ने यह फैसला पूर्वी लद्दाख में पड़ रही भीषण ठंड की वजह से किया है। जानकारी के अनुसार भारतीय सीमा के पास 200 किलोमीटर के दायरे से चीन ने अपने सैनिक हटाए

हैं। खबर के अनुसार सूत्रों ने बताया कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सीमा के पास उस इलाके में जहां चीनी सैनिक पारंपरिक रूप से प्रशिक्षण किया करते थे, अब वो जगह खाली दिख रही है। पिछले साल मार्च-अप्रैल के दौरान जब दोनों पक्षों के बीच तनाव जन्मा था, जब चीन ने सीमा पर 50 हजार सैनिक तैनात किए थे। तब से ये सैनिक वहीं तैनात थे। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग



सो के दक्षिणी किनारे पर शुक्रवार की सुबह चीन की जनमुक्ति सेना (पीएलए) के एक सैनिक को पकड़ा गया था जो वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पार कर भारत की तरफ

आ गया था। जानकारी के अनुसार पीएलए के सैनिक को सोमवार सुबह 10 बजकर 10 मिनट पर पूर्वी लद्दाख के चुशुल-मोल्डो सीमा बिंदु पर चीन को वापस सौंपा गया। इससे पहले 18 अक्टूबर को चीन-भारत सीमा पर एक चरवाहे की उसकी याक खोजने में मदद करने के दौरान एक सैनिक कथित तौर पर लापता हो गया था। भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख में आठ महीनों से

भी ज्यादा समय से गतिरोध बना हुआ है। यह गतिरोध पिछले साल मई में शुरू हुआ था जब पैंगोंग झील इलाके में दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी। शिंघुआ विश्वविद्यालय में चीन के नेशनल स्ट्रेटजी इंस्टीट्यूट के शोध विभाग के निदेशक कियान फेंग ने इसे लेकर कहा कि लापता चीनी सैनिक की वापसी दोनों देशों के बीच सीमा नियमन तंत्र पर बनी सहमति के अनुरूप हुई है।

The Food House

India's Mughlai, Chinese, Restaurant

9821927777 / 9987584086

ADDRESS: Squatters Colony, Chincholi Gate, Malad East, Mumbai-97

FREE HOME DELIVERY

zomato

SWIGGY

HALAL

fresh & easy

GENERAL STORE

ALL TYPES OF SAUDI DATES AVAILABLE

SPECIALIST IN: DRY FRUITS

& MANY MORE ITEMS AVAILABLE HERE

ADDRESS: +91 8652068644 / +91 7900061017

Shop No. 18, Parabha Apartment, Sejal Park, Beside Oshiwara Bus Depot, Link Road, Goregaon (W), Mumbai-400104

Fast & Free DELIVERY

राजस्थान हलचल

पत्नी के लिए आत्महत्या करने वाला पति गहने-कैश लूटकर हुआ फरार

संवाददाता/सैयद अलताफ हूसैन कोलकाता। फेसबुक से दोस्ती कर लड़की से शादी की और फिर धोखा देकर भाग गया शातिर धोखेबाज पति। जी हाँ, ये कहानी है कोलकाता की एक महिला की जिसने पेशान होकर एक साल बाद अपने धोखेबाज पति के घर पहुँचकर जमकर हंगामा काटा और यूपी की फतेहपुर पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। महिला का कहना है कि शादी से पहले यह आत्महत्या की धमकी देता था। वह कहता था कि तुम अगर शादी के लिए नहीं मानी तो ब्लेड से गर्दन काटकर आत्महत्या कर लूंगा। लेकिन अब वह धोखा देकर फरार हो गया है। महिला कि मांग है कि ऐसे शातिर लोगों को सलाखों के पीछे भेजा जाए। उसका कहना है कि शादी के बाद उसका पति घर में रखे सारे जेवरों सहित कैश लूटकर फरार हो गया। वहीं, पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही उसे अरेस्ट किया जाएगा। महिला ने पति की तलाश के लिए कोलकाता पुलिस के साथ आकर जिले की पुलिस से गुहार लगाई है। इसके बाद



महिला पुलिस के साथ पति अभिषेक आर्या के घर पहुँची। घर में ताला बंद देखकर महिला ने जमकर हंगामा काटा। पीड़िता दिपाली (बदला हुआ नाम) का कहना है कि अभिषेक आर्या से फेसबुक से दोस्ती हुई। जान पहचान के बाद दूर से पारिवारिक रिश्तेदार निकले। इसके कुछ दिन बाद अभिषेक शादी के लिए दबाव बनाने लगा। महिला का कहना है कि अभिषेक ने गले में ब्लेड लगाकर आत्महत्या करने की धमकी तक

दे डाली। उसका कहना था कि तुम नहीं मिली तो गर्दन काट लूंगा। फिर भी दिपाली ने इस बात को नजरअंदाज किया लेकिन अभिषेक दिल्ली से सीधे फ्लाइट पकड़ कोलकाता पहुँचा गया। इसके बाद कोलकाता पहुँचकर अभिषेक ने दिपाली को समझा-बुझा कर शादी के लिए मना लिया। उसके बाद दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और दोनों लोग होटल में रुके। महिला का कहना है कि अभिषेक के पिता राजू आर्या बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी करते हैं। जब यहाँ आकर देखा वे भी गायब हैं। यही नहीं, शातिर उसके घर के लॉकर में रखे 3 लाख के जेवर सहित 1 लाख नकद लेकर भाग गया है। वहीं, पीड़िता की माँ की मांग है कि ऐसे लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि वह किसी और लड़की की जिंदगी को बरबाद न कर सके। वहीं, एसपी सतपाल अतिल ने बताया कि कोलकाता पुलिस के साथ एक पीड़िता आई थी जिसके लिए कोतवाली पुलिस और डीएसपी सिटी को मदद के लिए लगाया गया है। जल्द ही आरोपी को अरेस्ट कर कोलकाता पुलिस को सौंप दिया जाएगा।

मारवाड़ शेख, सय्यद, मुगल पठान विकास समिति, जिला जोधपुर के अध्यक्ष पद पर उस्ताद हाजी हमीम बक्ष को सर्व समिति से घोषित किया



संवाददाता/सैयद अलताफ हूसैन जोधपुर। मारवाड़ शेख सैयद मुगल पठान जिला विकास समिति की एक बैठक बंबा बारी राजीव गांधी वाचनालय में कोम शेख सैयद

मुगल पठान के लोगो के साथ हूवी जिसमे कई कोम के गनमाणय लोग शामिल थे बैठक में सभी ने मिलकर भरोसा जता कर सर्व समिति से उस्ताद हाजी हमीम बक्ष को कोम शेख सैयद

मुगल पठान समाज जिला जोधपुर का अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जिसमे बैठक नियामत पठान उस्ताद अ वहीद खान शोएब खान रमजान अली पणू शकिल अहमद अजीज पठान फिरोज खान शकिल पठान से आरिफ अली राजू ईशतियाक अली भूर जी अमजद बक्ष उस्ताद शफी अनवर हुसेन अकबर जेके इकबाल खान राजू पठान नदिम बक्ष शाकिर शेख महसिन शेख माजिद खान बिलाल खान हेदर खान व कई कोम के मोजीज लोग व नोजवान शामिल थे।

अमरावती हलचल

हेल्थ कार्ड शिविर का सफल आयोजन



अमरावती। वंचित बहुजन आघाडी के नेता डा अलिम पटेल द्वारा लालखडी परिसर में तिन दिवसीय हेल्थ कार्ड शिविर आयोजित किया गया था 9/10/11 जनवरी को आयोजित इस शिविर का सैकड़ों लोगो ने लाभ उठाया इस हेल्थ कार्ड शिविर को आयुष्मान कार्ड के नाम से

जाना जाता है। डा अलिम पटेल ने इस शिविर के माध्यम से गरिब और जरूरतमंद नागरिकों की सहायता की जिसके कारण इन लोगों को सरकारी योजना के जरिये 5 लाख रुपये तक की सहायता उपचार हेतु मिल सकती है। आयोजक वंचित बहुजन आघाडी के जिला

अध्यक्ष डा अलिम पटेल, सिद्धार्थ गायकवाड, किरन डुडगे, मेजर हिदायत पटेल, मुजिब सर, सलिम भाई वेंडर, शेर ए हिंद के सलमान खान एटिएस, शोएब खान, रहिम राहि, मिर्जा शाहिद बेग, समिर भाई, असलम भाई आदि प्रमुखता से उपस्थित थे।

बुलडाणा हलचल

पोल्ट्री व्यवसाय, हो रहा अफवाहों का शिकार

संवाददाता/अशफाक युसुफ

बुलडाणा। राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों को कुक्कुट व्यवसाय में संलग्न होने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है क्योंकि कृषि नुकसान में है। लेकिन सरकार के पास इस तरह के संकट से निपटने के लिए कोई उपाय नहीं है, इस वर्ष कुक्कुट किसान आत्महत्या के कगार पर है। यह पिछले छह महीनों में दूसरी बार पूरी तरह से तबाह हो रहे पोल्ट्री मालिकों की दुर्भाग्यपूर्ण चिज है। इस संबंध में, सरकार के पास कोई डेटा उपलब्ध नहीं है या कुक्कुट धारकों की मदद करने के लिए कोई नीति सहायता नहीं मिल सकती। कोरोना ने फरवरी के अंत में देश में प्रवेश किया और 22 मार्च को लॉकडाउन शुरू हुआ। इससे पहले, यह अफवाह थी कि कोरोना एक चिकन के कारण फैल रहा है। नतीजतन, कोरोना आपदा से पहले पोल्ट्री व्यवसाय एक खसारे में चला गया, जिस से पोल्ट्री किसानों सड़कों पर आ गए। उसके बाद, सरकार ने खुद यह सुझाव नहीं दिया कि अंडे और चिकन का सेवन किया जाना चाहिए क्योंकि वे न केवल उपयोगी हैं बल्कि प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने में भी बहुत प्रभावी हैं। इतना ही नहीं, प्रत्येक कोविड केंद्र में, रोगियों को सरकार द्वारा स्वयं अंडे दिए जाते थे, जो एक तथ्य भी है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि कोरोना और चिकन के बीच कोई संबंध नहीं था अब फिर से वही प्रकार बर्ड फ्लू के मामले सामने आ रहे हैं। अभी तक महाराष्ट्र में एक भी मुर्गी बर्ड फ्लू से संक्रमित नहीं हुई है। आज तक, राज्य में बगुले, कौवे और तोते सहित कुछ पक्षियों को देखा गया है, लेकिन अगर मुर्गियाँ मर जाती हैं, तो एक ही बार में आठ से दस मुर्गियाँ मारे जाने का कोई उदाहरण नहीं है लेकिन फिर भी, मीडिया मृत तोते, कौवे को दिखाता है और सीधे मुर्गियों से जोड़ दिया जाता है। इसलिए, दुर्भाग्यपूर्ण चिज यह है कि पोल्ट्री व्यवसाय, जो कि करोड़ों रुपये का उद्योग है, केवल अफवाहों का शिकार हो रहा है।



वर्तमान में बुलडाणा जिले में कोई बर्ड फ्लू बिमारी नहीं है: डॉ. ज्योति खरे

बुलडाणा। बर्ड फ्लू की अफवाहों पर जिले के लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। अभी तक जनता कोरोना वायरस को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। लोगों द्वारा फैलाई जा रही अफवाहों के मद्देनजर जिले के लोग भी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इस सिलसिले में जिला पशुपालन विभाग के सहायक उपायुक्त डॉ. ज्योति खरे ने कहा जिले में इस समय कोई बर्ड फ्लू की सूचना नहीं मिली है और जिले में स्थिति पर नजर रखने के लिए 14 त्वरित शीघ्र कृती पथके बनाए गए हैं। इसकी सूचना जिला पशुपालन के सहायक उपायुक्त डॉ. ज्योति खरे इन्होंने दिया है।

रामपुर हलचल

लहर हाई फसलों एवं फलों के बागात में किया जा रहा कीटनाशक जहरीले पदार्थों का प्रयोग

संवाददाता नदीम अख्तर

टाण्डा (रामपुर)। लहर हाई फसलों एवं फलों के बागात में किया जा रहा कीटनाशक जहरीले पदार्थों का प्रयोग छोटे छोटे-छोटे जानवर एवं पक्षी फसलों के कीटनाशक दाने खाने से लगातार होते जा रहे हैं मृत्यु का शिकार, खाद्य सामग्री दूध आदि जैसे प्रयोग में लाया जा रहा है अनेकों प्रकार के घुलन शील पदार्थ जो जहरीले में होकर जिनका किया जा रहा है रोजाना प्रयोग, तरह तरह की बिमारीयां पनपने का कोई ध्यान, कीटनाशक पर राके लगाये जाने के बजाय किया जा रहा है लगातार प्रयोग। पहले समय में फसलों आदि बागात में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न कर मात्र घरेलू खाद का ही प्रयोग किया जाता था आज के समय में खेती एवं फसलों बागात में खुलैआम कीटनाशक दवाओं का ही प्रयोग किया जा रहा है। जिसके प्रयोग से कीटनाशक दवाओं के असरात मनुष्य एवं पक्षियों के अन्दर पहुँचते हैं उनके अन्दर खुलैआम जहर घुलता नजर आ रहा है जिससे अनेकों प्रकार की गम्भीर बीमारियों ने अपना घर बनाना शुरू कर दिया है जो जल्द ही मौत का शिकार होने की कगार पर है। दूध दही एवं अन्य प्रकार की खाद्य सामग्रीयों में मिलाये जाने वाला कोमिकल जो जहर के ही समान है मनुष्य के जीवन अपना बुरी तरह प्रभाव डालता है जिससे मनुष्य का लीवर एवं किडनी बेकार होकर रह जाती है जिससे ब्लड का आना जाना व कम होने की कगार पर हो जाता है। जिनका नियंत्रण कर पाना कठिन कार्य साबित हो पा रहा है। खान पान जैसी वस्तुएँ आज के समय में खाने लायक नहीं हैं जिनपर रोक लगा पाना साथ ही सरकार का इस ओर कोई खास तवज्जो नहीं है जिनपर सुधार किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

लोग क्यों खाने लगे हैं आर्गेनिक फूड्स क्या है इसके फायदे

ऑर्गेनिक फूड खाने के फायदे : माण-दौड़ और तनावमयी जिंदगी के कारण लोगों के पास इतना भी समय नहीं की वह अपने खान-पान पर ध्यान दे सके। कई लोग पेट भरने के लिए प्रोसेस्ड और डिब्बाबंद खाना खा रहे हैं। मगर इस तरह के खाने को खाने से छोटी उम्र में ही डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कैंसर जैसी बीमारियां होने लगी हैं। इन बीमारियों से बचने के लिए कुछ लोगों ने ऑर्गेनिक फूड्स को खाना शुरू कर दिया है। उन लोगों का मानना है कि इनमें विटामिन, मिनेरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन आदि जरूरी तत्व मौजूद होते हैं। इसलिए इनको खाना हैल्दी रहता है।

क्या होता है ऑर्गेनिक फूड

ऑर्गेनिक फूड को तैयार करे के लिए किसी भी कैमिकल युक्त दवाई का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इनको उगाने या बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के रसायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किया। ऑर्गेनिक फूड को नेचुरल तरीके से बढ़ने दिया जाता है। आम फूड आइटम्स और ऑर्गेनिक फूड आइटम्स के बीच फर्क कर पाना मुश्किल है क्योंकि रंग और आकार में ये एक जैसे ही दिखते हैं।

ऐसे पहचानें ऑर्गेनिक फूड

ऑर्गेनिक फूड और आम फूड्स देखने में एक जैसे ही लगते हैं। मगर ऑर्गेनिक फूड में सर्टिफाइड स्टिकर्स लगे हैं। स्टिकर्स लगने के साथ ही इन फूड्स का स्वाद भी कुछ अलग होता। ऑर्गेनिक मसालों की गंध आम मसालों से ज्यादा होती है। इसके साथ तरह-तरह ऑर्गेनिक सब्जियां गलने में ज्यादा टाइम नहीं लेती। जल्दी पक जाती हैं।

बीमारियों से बचाएं

ऑर्गेनिक फूड को तैयार करने के लिए किसी भी कैमिकल युक्त दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए इसमें सारे पौषक तत्व मौजूद होते हैं। इनको खाने से ब्लड प्रेशर की समस्या, माइग्रेन, डायबिटीज और कैंसर जैसी समस्याएं नहीं होती। इसके साथ इनका सेवन करने से रोग-प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। इसमें इन फूड्स में फैट की मात्रा भी बहुत कम होती है। इसके अलावा रोजाना ऑर्गेनिक फूड्स खाने से स्किन पर निखार आता है।

फूड्स खरीदते समय इन बातों को रखें ध्यान

ऑर्गेनिक फूड्स वहीं से खरीदें जहां पर इसकी प्रमाणिकता साबित हो। आमतौर पर ऑर्गेनिक दालों में कीड़ा लगने की शिकायत भी नहीं आती। पैकेट पर लिखी जानकारी ध्यान जरूर पढ़ लें।



इन 10 प्रॉब्लम्स को दूर रखने के लिए आपको भी पीनी चाहिए पुदीने की चाय

शीन टी पीने के फायदे : बिजी लाइफस्टाइल में किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि वह अपनी सेहत का ध्यान रख सके। गलत खान-पान और हैल्थ के प्रति बरती गई थोड़ी-सी असावधानी से आपको कई समस्याएं होने लगती हैं। इससे बचने के लिए सही डाइट का होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग अपने दिन की शुरुआत शीन टी से करते हैं लेकिन इससे भी ज्यादा फायदेमंद है पुदीने की चाय। आज हम आपको स्पेअरमिंट टी यानी पुदीने की चाय के बारे में बताएंगे, जिससे आप कई बीमारियों से बच सकते हैं। तो आइए जानते हैं स्पेअरमिंट टी पीने के फायदे। स्पेअरमिंट एक तरह का पुदीना ही है। मगर यह पहाड़ों में पाया जाता है। इसकी पैदाइश मूलरूप से यूरोप में हुई थी। पर अपने गुणों की बदौलत आज इसे संसारभर के लोग पी रहे हैं। इसको पीने के कई फायदे होते हैं। आज हम आपको स्पेअरमिंट टी पीने के फायदे बताएंगे।



1. इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होना

जो लोग अक्सर बीमार रहते हैं उनके स्पेअरमिंट टी पीनी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें पाए जाने वाले पौषक तत्व रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होता है। इसके साथ ही रोजाना 1 कप स्पेअरमिंट टी पीने से पाचन तंत्र, यूरिन से होने वाली जलन और सांस संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है।

2. पीसीओएस में हैल्पफूल

शरीर और चेहरे पर अत्यधिक बालों का होना, यौन इच्छा में अचानक कमी, युवावस्था या प्रजनन की उम्र के दौरान अनियमित मासिक धर्म का होना, शारीरिक महिलाओं में बांझपन या गर्भ न ठहरना जैसे लक्षण दिखाई दें तो ये पीसीओएस के लक्षण हैं। इस बीमारी से बचने के लिए रोजाना 1 कप स्पेअरमिंट



4. पेट की समस्याओं को करें दूर

यह टी हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करती है। इसके साथ यह पेट में बनने वाली गैस और दर्द से भी राहत दिलाती है। इसके अलावा स्पेअरमिंट टी पाचन क्रिया को सुधारी है और भोजन को पचाने में भी मदद करती है।

5. सांसों की बदबू मिटाएं

बार-बार ब्रश करने के बाद भी सांसों से बदबू आने लगती है। ऐसा सल्फाइड और अमाइन के कारण होता है। स्पेअरमिंट टी के गुण सांसों की बदबू पैदा करने वाले पदार्थों को बढ़ने से रोकता है। अपनी डाइट में इस चाय को शामिल करने

टी पीएं।

3. ऑस्टियोआर्थराइटिस को करें कम

स्पेअरमिंट टी में एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो सूजन को कम करने का काम करता है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या है तो इस टी को पीना शुरू करें। इसको पीने से कुछ ही दिनों में जोड़ों में होने वाले दर्द से राहत मिलेगी।

से सांसों की बदबू मिटाने लगती है।

6. फंगल इन्फेक्शन रोके

स्पेअरमिंट टी में एंटी-फंगल गुण होते हैं फंगल इन्फेक्शन से लड़ने में सहायक है। रोजाना 1 कप यह टी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होने के साथ ही फंगल इन्फेक्शन होने का भी खतरा कम रहता है।

7. तनाव से राहत दिलाएं

प्राकृतिक एंटी-स्पास्मोडिक गुण है जो तनाव से राहत देने के लिए अच्छा होता है। इसके प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण ब्लड प्रेशर और शरीर के तापमान को कम करने में मदद करते हैं और आपको आराम देते हैं।

8. लीवर रखें स्वस्थ

एक रिसर्च में पाया गया है कि स्पेअरमिंट टी पीने से लीवर मजबूत होता है। अगर आपको भी लीवर से संबंधित कोई समस्या है तो इस चाय को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।

9. कैंसर से बचाव

फ्री रेडिकल को सेलुलर ब्रेकडाउन का प्राथमिक कारण माना जाता है जो पुरानी बीमारियों के कारण होता है। कैंसर भी इसी वजह से होता है। एक शोध में पाया गया है कि स्पेअरमिंट टी में एंटी-ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो फ्री रेडिकल को खत्म करते हैं। कैंसर से बचाव के लिए रोजाना यह चाय पीएं।



वरुण धवन बोले- उम्मीद है 2021 में कर लूंगा नताशा दलाल से शादी

पिछले काफी समय से बॉलिवुड ऐक्टर वरुण धवन और उनकी लॉन्ग-टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल की शादी के कयास लगाए जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि यह कपल 2020 में शादी कर सकता है लेकिन पिछले साल कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन में वरुण और नताशा की शादी नहीं हो सकी। अब वरुण धवन ने उम्मीद जताई है कि वह 2021 में नताशा दलाल से शादी कर लेंगे। हमारे सहयोगी 'फिल्मफेयर' को दिए एक इंटरव्यू में वरुण धवन ने अपनी शादी के प्लान पर चर्चा की। उन्होंने कहा, 'हर कोई पिछले 2 सालों से मेरी शादी के बारे में बात कर रहा है। अभी तक कुछ तय नहीं है। अभी दुनिया में बहुत अनिश्चितता है लेकिन अगर चीजें ठीक होती हैं तो शायद इस साल मैं शादी कर लूंगा। मेरा मतलब है कि मैं इसकी प्लानिंग जल्द ही करूंगा लेकिन अभी थोड़ा माहौल निश्चित होने दीजिए।' वर्क फ्रंट की बात करें तो कुछ दिन पहले ही वरुण धवन और सारा अली खान की फिल्म 'कुली नंबर 1' रिलीज हुई थी जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स ने कुछ खास पसंद नहीं किया था। हाल में वरुण ने अपनी अगली फिल्म 'जुग जुग जियो' के फर्स्ट शेड्यूल की शूटिंग पूरी की है। इस फिल्म में वरुण धवन के साथ कियारा आडवाणी, अनिल कपूर और नीतू कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं।



बॉबी देओल की फिल्म सोलजर का बनेगा रीमेक!

बॉबी देओल का कमबैक शानदार रहा है। रेंस 3, हाउसफुल 4 जैसी फिल्मों के अलावा आश्रम नामक उनकी वेबसीरिज भी सुपरहिट रही। 2020 में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली सीरिज आश्रम ही रही। एक बार फिर बॉबी के करियर में उछाल आ गया है और फिल्म निमाताओं के बीच उनकी मांग बढ़ गई है। इस बात से डेड धर्मेन्द्र और भाई सनी देओल काफी खुश हैं क्योंकि जब बॉबी के पास काम नहीं था और वे डिप्रेशन में आ गए थे और शराब के घाले में उन्होंने अपने आपको डूबो लिया था। खुद बॉबी को एक दिन शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने फिर से करियर संवारने का फैसला किया और नतीजा सामने है। खबर है कि बॉबी की बढ़ती डिमांड को देख उनकी सुपरहिट फिल्म सोलजर के सीक्वल का प्लान बनाया जा रहा है। यह फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी और उस वर्ष बॉक्स ऑफिस पर सर्वाधिक कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रही थी। सोलजर में बॉबी के अलावा प्रीति जिंटा, राखी, फरीदा जलाल, जॉनी लीवर, सुरेश ओबेरॉय, आशीष विद्यार्थी जैसे कलाकार थे। अब्बास-मस्तान ने अपनी चिर-परिचित शैली में थ्रिलर बनाई थी। फिल्म में संगीत अनु मलिक का था और कई गाने हिट रहे थे। सूत्रों के अनुसार सोलजर का सीक्वल पर फिलहाल विचार चल रहा है और सभी पहलुओं पर गौर कर ही आगे बढ़ा जाएगा। बॉबी और प्रीति के अलावा कुछ नए चेहरे भी जोड़े जाएंगे।

कंगना रनौत को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत

बॉलिवुड ऐक्ट्रेस कंगना रनौत को बड़ी राहत देते हुए सोमवार 11 जनवरी 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने राजद्रोह के केस में 25 जनवरी तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली पर मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में 124ए (राजद्रोह), 295ए और 153ए के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बांद्रा कोर्ट ने कार्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ सेथ्यद की शिकायत के बाद कंगना और उनकी बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे। खबर के मुताबिक, कंगना और उनकी बहन रंगोली ने अपने टवीट्स के जरिए सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने और महाराष्ट्र सरकार का नाम बदनाम करने का काम किया है। वहीं, कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि कंगना लगातार बॉलिवुड को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से लेकर टीवी तक, हर जगह वह इंडस्ट्री के खिलाफ बोल रही हैं। यही नहीं, याचिका में आरोप लगाया गया था कि कंगना ने बॉलिवुड के हिंदू और मुस्लिम कलाकारों के बीच खाई पैदा की है।

